>

Title: Need to cancel the allocation of coal mines to private sector in

Palamu district of Jharkhand.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया द्वारा अभी तक 269 कोल ब्लॉक को प्राईवेट कम्पनी को दे दिया गया है। कोल श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं प्राईवेट मालिकों के शोषण से निजात दिलाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था जिससे एक तरफ तो कोयला श्रमिकों के हित को ध्यान में रखा गया था, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सम्पत्ति का दोहन गैर नियंत्रित एवं असुरक्षित ढंग से न हो इसका ध्यान रखा गया था और सच्चाई यह भी है कि कोल इंडिया ने अपने कुशल कर्मचारियों के जरिये दुर्घटना रहित गुणवत्ता पूर्ण कोयले की निकासी की है और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है।

अभी पता चला है कि झारखण्ड राज्य के सीसीएल के राजहरा क्षेत्र के राजहरा कोलियरी का उत्तरी पूर्वी भाग "मुकुन्द लिमिटेड " एवं "विन्नी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड " एवं होरिलॉग परियोजना रूंगटा को दे दिया गया है।

झारखण्ड राज्य का पलामू प्रमण्डल बहुत ही पिछड़ा एवं गरीब इलाका है जिसमें 80 प्रतिशत गरीब आदिवासी एवं अति पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं। इस कोलियरी के प्राईवेट में चले जाने से हजारों नियमित मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे जैसा कि सीसीएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशक तकनीकी संचालन ने अपने पत्रांक सीसीएल/सीएपी/माइन/2087-2089 दिनांक 29.11.07 एवं डीटीपीएनपी/2008/18/10 दिनांक 10.11.2008 के द्वारा उसे सत्यापित किया है। अतः हम यह मांग करते हैं कि उपरोक्त का आबंटन शीघ्र रद्द किया जाये।